Meeting of the Inter-State Council held on July 17, 1997, it was decided to accept the recommendations of the Tenth Finance Commission in this regard subject to certain modifications. However, the Lok Sabha was dissolved before the Constitution Amendment Bill could be introduced.

The present Government has ratified the decision taken by the previous Governfment. This was announced in FM's Budget Speech. the Constitution Amendment Bill was introduced in Lok Sabha on 14th July, 1998. Hon'ble Speaker has referred the Bill to the Standing Committee on Finance.

रुपये का अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन

*333. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपये को अवमूल्यन से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) वर्ष 1971 को आधार वर्ष मानते हुए भारतीय रुपये की क्रय शक्ति अक्टूबर, 1998 तक वर्ष-वार कितनी-कितनी थी; और

(ग) भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन हेतु क्या मापदंड निर्धारित किया गया है तथा क्या भारतीय क्रय शक्ति भी एक आधार है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ग) भारत में रुपए की विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है तथा भुगतान संतुलन के चालू और पूंजी दोनों खातों पर विदेशी मुद्रा की आवा-जाही की प्रवृत्तियों के साथ-साथ अल्प-कालिक सट्टे की स्थिति द्वारा प्रभावित होती है। विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपए में उतार-चढ़ाव भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजारों में इन मुद्राओं के उतार-चढ़ाव को कुछ सीमा तक प्रतिबिम्बित करता है।

विनिमय दर उतार-चढ़ाव का सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आर० बी० आई०) दोनों द्वारा बारीकी से अनुवीक्षण किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक, जब कभी आवश्यक हो, विदेशी विनिमय बाजारों में हस्तक्षेप करता है और रुपए पर अनिश्चित दबावों को रोकने तथा विदेशी मुद्रा बाजार की सुव्यवस्थित स्थितियां सुनिश्चत करने के लिए उपयुक्त मौद्रिक और अन्य उपाय लागू करता है। इन उपायों से बाह्य दबावों की अवधि के दौरान रुपए के विदेशी मूल्य में उचित स्थिरता को बनाए रखने और भारत की विदेशी प्रतिस्पर्द्धात्मकता के संरक्षण और उसमें सुधार लाने के अनुकूल विनिमय दर के स्तर को बनाए रखने में मदद मिली है।

(ख) 1971 के आधार पर औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी०पी० आई०) के रूप में, 1971 से अक्टूबर, 1998 तक रुपए के घरेलू मूल्य की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1971 के आधार पर पैसे में रुपए का मूल्य

वर्ष/महीना	सी०पी०आई० (आई०डब्ल्यू०) 1971 पर आधारित	रुपए का मूल्य (पैसे में)
1971	100	100.00
1972	106	94.26
1973	124	80.46
1974	160	62.58
1975	169	59.21
1976	156	64.15
1977	169	59.21
1978	173	57.73
1979	184	54.34
1980	205	48.72
1981	232	43.08
1982	259	38.54
1983	285	35.04
1984	306	32.66
1985	322	31.08
1986	348	28.74
1987	378	26.43
1988	414	24.14
1989	444	22.54
1990	483	20.70
1991	550	18.18
1992	615	16.26
1993	654	15.29
1994	719	13.91
1995	794	12.59

1996	867	11.54
1997	929	10.77
जनवरी, 98	996	10.04
फरवरी, 98	991	10.09
मार्च, 98	986	10.14
अप्रैल, 98	994	10.06
मई, 98	1009	9.91
जून, 98	1035	9.66
जुलाई, 98	1066	9.38
अगस्त, 98	1072	9.33
सितम्बर, 98	1090	9.18
अक्टूबर, 98	1124	8.90

Postponement of Disinvestment

*334. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are thinking of postponement of disinvestment plea due to poor market conditions;

(b) if so, what would be its impact on the budget; and

(c) if not, which are the PSUs equity of which will be dis-invested during the next three months and the percentage of disinvestment?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Partial disinvestment of Government equity in GAIL, VSNL and IOC are eavisaged during the next three months. Percentage of disinvestment will be decided near the time of launching of the issues.

Foreign Loans

*335. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the details of foreign loans taken by Government from various countries and agencies like IMF, World Bank etc., till 1998;

(b) the details of interest and principal amount being paid as repayment annually by Government to various countries and agencies;

(c) the details of outstanding amount due till June, 1998; and

(d) the details of foreign loan proposed to be taken from various countries and other agencies under different heads?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) to (d) The information is given in Annexure [*See* Appendix 185, Annexure No. 63]

Development of minor ports in Maharashtra

*336. SHRI SANJAY MIRUPAM: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Government of Maharashtra has sent proposals seeking Central assistance to the tune of 50 per cent of expenditure on development of minor ports in Maharashtra;

(b) the total amount demanded by the Maharashtra Government for development of minor ports; and

(c) when the Central Government are likely to release the amount demanded by the State Government?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS AND MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) Yes, Sir.

(b) Fifty percent of Rs. 1,76,70,417/- spent by the State Government on feasibility studies for 7 minor ports in Maharashtra.

(c) Release of funds will be considered subject to availability of appropriate budget provision in the Central Government budget.